



मध्य प्रांत के जनजागरण में आदिवासी नायकों की भूमिका: छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में

डॉ. रामानुज प्रताप सिंह धुर्वे

सहायक प्राध्यापक इतिहास

शास.बा.सा.दे.महा.कुनकुरी जिला जशपुर, (छ.ग.)

सारांश:

भारत के हृदय में स्थित मध्यप्रांत अतीत से ऐतिहासिक व संस्कृतिक दृष्टि से वैभव सम्पन्न रहा है। मध्यप्रांत के छत्तीसगढ़ की पहचान सदैव आदिवासी बहुल राज्य के रूप में रही है। यहाँ की संस्कृति जनजातीय विशेषता ली हुई हैं। यहाँ गोंड, कंवर, हल्बा, उरांव आदि अनेक जनजाति निवास करते हैं। इन जनजातियों ने न केवल छत्तीसगढ़ को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया है वरन ऐतिहासिक रूप से मध्यप्रांत के जनजागरण में महत्ती भूमिका निभाई है। भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन के बाद देश के हर हिस्से में ब्रिटिश साम्राज्य को आदिवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी आर्थिक नीतियों ने आदिवासियों की जीवन प्रणाली को तहस नहस कर डाला था। अंग्रेजों के निरंतर शोषण और अत्याचारों के विरुद्ध जब भारतीयों ने बगावत का बिगुल फुंका तब मध्यप्रांत भी इस से अछूता नहीं रहा। मध्यप्रांत के छत्तीसगढ़ संभाग में राजनीतिक चेतना को प्रारंभ करने का श्रेय आदिवासियों को ही जाता है। मध्यप्रांत के छत्तीसगढ़ संभाग अंग्रेजों के विरुद्ध आरम्भिक विद्रोह का नेतृत्व आदिवासी समुदाय ने ही किया।

प्रस्तावना:

सीताबर्डी के युद्ध में भोंसले की पराजय उपरांत नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य का अप्रत्यक्ष हिस्सा बन गया। छत्तीसगढ़ का शासन ब्रिटिश संरक्षण में आ गया। ब्रिटिश संरक्षण में आने के उपरांत मध्यप्रांत व बेरार में उस शोषण की शुरुआत हुई जो पहले कभी नहीं रहीं। अंग्रेजों ने यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, आर्थिक नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन कर डाले। यहाँ रहने वाले आदिवासी जंगलों से गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। अंग्रेजों ने उस पर भी

CORRESPONDING AUTHOR:

Dr. Ramanuj Pratap Singh Dhurve

Asst. Professor - Dept. of History

Govt. Bala Saheb Deshpande College, Kunkuri, Dist. Jashpur, Chattisgarh

Email: r4ramanuj.singh@gmail.com

RESEARCH ARTICLE

अधिकार कर उनमें अनेक प्रतिबंध लगा दिए। मध्यप्रांत की भोली भाली आदिवासी जनता कब तक इस दमन को चुपचाप सहती। मध्यप्रांत व बरार के छत्तीसगढ़ संभाग में हमें अनेक आदिवासी विद्रोहों की जानकारी प्राप्त होती है।

मध्य प्रांत व बरार:

औपनिवेशिक भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रांत व बरार ब्रिटिश काल का प्रमुख प्रांत था। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व यह मात्र भिन्न-भिन्न भौगोलिक ईकाइयाँ थी। अंग्रेजों ने इन विभिन्न भौगोलिक ईकाइयों को जोड़कर मध्यप्रांत व बरार का निर्माण किया था। प्रांत गठन के पूर्व मध्यप्रांत दो विभिन्न प्रांतों का हिस्सा था। सागर नर्मदा के क्षेत्र उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था। वहीं छत्तीसगढ़ व विदर्भ का क्षेत्र नागपुर के भोंसले राजाओं के अधिकार में था। मध्यप्रांत के गठन के लिए लार्ड कैनिंग ने उत्तर पश्चिमी प्रांत के सागर नर्मदा क्षेत्र को 1854 ई. में मराठों से छीनकर नागपुर राज्य में मिला दिया था। दोनों क्षेत्रों का यह विलय 1861 ई. में हुआ था। विलय के पश्चात यह क्षेत्र मध्य प्रांत के रूप में जाना गया। सोनाखान के जमींदार का विद्रोह

सोनाखान जमींदारी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्थित है। ब्रिटिश शासन काल में यह जमींदारी रायपुर जिले में स्थित थी। सोनाखान जमींदारी हैहय शासकों द्वारा सैनिक सेवा के रूप में प्रदान की गयी थी, मराठा काल में यह आश्रित राज्य में परिवर्तित हो गयी थी। यह बिंझवार जनजाति के अधीन थी। यह जमींदारी 75 रुपये टकोली पड़ता था। सोनाखान जमींदारी ने हमेशा पराक्रम, स्वधर्म और देशभक्ति का परिचय दिया है। यह जमींदारी राजा बहार साय के समय लगभग 1490 में आदिवासी अंग्रेजों के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया था। 1818 में सोनाखान में सहासी जमींदार रामराय का शासन था। छत्तीसगढ़ के सूबेदार की अपेक्षा रामराय का आदेश अधिक माना जाता था। यह बात अंग्रेज शासकों को रास नहीं आई व छल एवं बल से उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे।

अंग्रेजों और सोनाखान जमींदारी के संघर्ष की शुरुआत 1819 में हुई। रामराय ने 1819 ई में अंग्रेजों की सत्ता व उसके कानून को मानने से इंकार कर दिया। रामराय का इस इलाके में इत्ता प्रभाव था कि लोग अंग्रेज सत्ता के आदेश का उल्लंघन कर सकते थे किंतु रामराय का नहीं। अंग्रेजों ने रामराय पर आरोप लगाया कि रामराय अंग्रेजों की खिलाफत करने वालों को शरण देता है और आसपास आतंक फैलाये हुए है। दरअसल रामराय उन समस्त भूमि को वापस लेने पर अड़ा था जो कभी उसके पूर्वजों के अधीन थे, जिसे भोंसले और अंग्रेजों ने उनसे छीन लिया गया था। रिचर्ड जेनकिन्स अपनी रिपोर्ट में रामराय की शक्ति का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि “रामराय व रामराय के पिता स्वयं एक छोटी सी जामींदारी के मालिक थे किन्तु लम्बे समय तक वे छत्तीसगढ़ के अनेक गाँवों में आक्रमण कर अपने अधिन अनेक खालसा भूमियों को अधिग्रहित कर लिया था। रामराय ने अपने आस-पास की जमींदारियों से भी कई गाँव छिन लिए थे।” मि. जेनकिन्स ने कंपनी अधिकारियों को खत लिखा था कि “सोनाखान का जमींदार परिवार विदेशी प्रभुता को पसंद नहीं करता है। रामराय के पिता और स्वयं रामराय छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन के लिए आतंक है”।¹ रामराय ने लगभग 300 गाँवों पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों की नजर में यह बड़ा ही दुस्साहस कार्य था वह भी सोनाखान जैसे छोटे से जमींदार द्वारा यह कार्य को अंजाम दिया जा रहा था।

संघर्ष का कारण

ब्रिटिश शासन व सोनाखान जमींदारी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण सोनाखान द्वारा ब्रिटिश शासन के भागोडों को शरण देना व विभिन्न क्षेत्रों से लूटी हुई सम्पत्तियों को रखने का स्थान बन गया था।

अतः 1819 में अंग्रेजों ने सोनाखान पर आक्रमण कर दिया और सोनाखान जमींदारी के बढ़ते प्रभाव को रोकने का प्रयास किया। रामराय अंग्रेजी ताकत का सामना नहीं कर सके और उन्हें कैप्टन मेक्सन के सम्मुख पराजय स्वीकार करना पड़ा। अंग्रेजों की सत्ता के सामने सोनाखान एक छोटी सी जमींदारी थी रामराय को परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ा किन्तु एक महत्वपूर्ण सन्धि के तहत सोनाखान जमींदारी रामराय को वापस कर दी गयी। 1819 में पराजित होने के उपरांत सोनाखान जमींदारी की शक्ति 300 ग्रामों से घटाकर 50 ग्रामों तक सीमित कर दी गयी फिर भी यह संधि रामराय के दबदबे को खत्म नहीं कर सका और बिंझवार के तलवार का जादू सिर चढ़कर बोलता रहा।²

परलकोट विद्रोह

परलकोट जमींदारी बस्तर राज्य के उत्तर पश्चिमी प्रदेश में स्थित थी। कोटरी, निबरा और गुडरा नदियों के संगम पर स्थित परलकोट सप्त मड़िया राज्यों में से एक था। 1908 ई में इसका कुल क्षेत्रफल 640 वर्ग मील था तथा इसकी जनसंख्या 1901 के अनुसार 5920 थी। परलकोट जमींदारी का मुख्यालय परलकोट गांव था। मि एग्न्यु के समय यहाँ का जमींदार गेंदसिंह हल्बा था। यहाँ के अधिकतर निवासी अबुझमाड़िया आदिवासी थे। इस विद्रोह का प्रमुख कारण था कि अबुझमाड़िया आदिवासी मराठों व अंग्रेजों के लूट खसोट की नीति से तंग आ चुके थे। बस्तर में मराठों व अंग्रेज अधिकारियों की उपस्थिति से वहाँ के आदिवासियों को अपनी पहचान का खतरा उत्पन्न होने लगा। विद्रोह का एक प्रमुख कारण मराठा सरकार द्वारा लगा एगएनए टैक्स भी थे। अबुझमाड़िया आदिवासियों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह सुगमता से टैक्स का भुगतान कर सके। अबुझमाड़िया आदिवासियों ने जब अपने शोषण का अंत होते नहीं देखा तो उन्होंने विद्रोह कर दिया।³

परलकोट विद्रोह 1824 ई. में हुआ था और इसका नेतृत्व परलकोट के जमींदार गेंदसिंह ने किया था। 24 दिसम्बर 1824 को बस्तर के अबुझमाड़िया आदिवासी परलकोट में एकत्र होने लगे। चार जनवरी 1825 तक यह समुदाय अबुझमाड से चांदा महाराष्ट्र तक छा गया। चूँकि इनका विद्रोह अंग्रेज और मराठों की जंगल विरोधी नीतियों से था अतः इन्होंने अपने विद्रोह संदेश के प्रसारण का तरीका भी जंगल में ही खोल लिया था। क्रान्तिकारी आदिवासी धावड़ा वृक्ष की टहनियों को संकेत स्वरूप एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते थे। इसका आशय था कि धावड़ा के पत्ते सूखने से पहले ये लोग निर्धारित स्थान पर पहुंच जाए।⁴ विद्रोह की भयावहता को देखते हुए तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासक मि एग्न्यु ने चांदा राज्य से सैन्य टुकड़ी को बुलवाया था। मराठों व ब्रिटिश सेना की संयुक्त टुकड़ी ने 10 फरवरी 1825 को परलकोट को घेर लिया। गेंद सिंह को बन्दी बना लिया गया और 20 जनवरी 1825 को परलकोट में उन्हें फांसी दे दी गयी। इस प्रकार परलकोट विद्रोह का दमन कर दिया।⁵

जंगल सत्याग्रह के अग्रदूत

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ की जो उल्लेखनीय बात है वो है असहयोग आन्दोलन का प्रारंभ, महात्मा गांधी के पहले ही छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह 1922 में सिहावा नगरी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सम्पूर्ण मध्यप्रांत में वन सत्याग्रह हो रहे थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशिष्ट पहचान बने रहे और कांग्रेस पार्टी का यह मुख्य आंदोलन बना रहा। सिहावा नगरी आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता श्री श्यामलाल सोम थे। श्री श्यामलाल सोम सिहावा जंगल सत्याग्रह के जनक थे जिन्हें मध्यप्रांत और बरार में जंगल सत्याग्रह का अग्रज मना गया है।

श्री श्यामलाल सोम का जन्म 1906 में हल्बा आदिवासी परिवार में हुआ था। 1919 में 14 वर्षीय श्यामलाल सोम रायपुर के नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे थे। गांधी जी के हृदय स्पर्शी भाषण का इनके किशोर मन में व्यापक प्रभाव पड़ा। वे नॉर्मल स्कूल की पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन के सत्याग्रही बन गए। श्यामलाल सोम व पंचम सिंह के नेतृत्व में सिहावा नगरी क्षेत्र में सत्याग्रही टोलियां तैयार होने लगीं। 1922 में सिहावा नगरी क्षेत्र के आसपास के गांवों में वन विभाग की नीतियों से त्रस्त होकर आसपास के एक दर्जन से अधिक गांवों के लोगों ने जंगल सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। आंदोलनकारियों का प्रमुख उद्देश्य आदिवासियों को वनों से उनका निस्तारी हक दिलाना था। निस्तार का अर्थ यह है कि आदिवासी वर्ग को वनों से हर तरह की वनोपज जिसमें जलाऊ और इमारती लकड़ी बांस आदि शामिल था। मुफ्त लेने का अधिकार था। वे अपने पशुओं को भी बिना रोकटोक के जंगलों में चरा सकते थे। अंग्रेजों ने अपने व्यवसायिक लाभ के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा वे आदिवासियों से बेगार करवाते थे।⁶

जंगल सत्याग्रही हर तरह से जंगल नियमों का उल्लंघन करते वे जंगल जाकर लकड़ी, बांस, घास काटकर और अपने मवेशी जंगलों में चराते थे। श्री श्यामलाल सोम के नेतृत्व में यह आंदोलन तीन सप्ताह तक चला। अंग्रेजों ने 33 शीर्ष व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था जिसमें अधिकतर आदिवासी शामिल थे। इन सत्याग्रहियों को तीन माह से आठ माह तक के कारावास की सजा सुनाई गई थी।⁷

निष्कर्ष:

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मध्यप्रांत के आदिवासियों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया था। छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा क्षेत्र जनजातीय बहुल है। इन जनजातीय नायकों ने ही अपने नेतृत्व गुण के माध्यम से आदिवासी समाज ही नहीं वरन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। स्वतंत्रता सेनानियों की इन पहली पीढ़ी को देखकर ही सम्पूर्ण समाज में राजीतिक चेतना आयी और राजनीतिक आंदोलनों को एक नयी धार मिली। 1857 की क्रांति के पहले भी छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था। 1857 की क्रांति की मशाल मध्यप्रांत के छत्तीसगढ़ में आदिवासी योद्धाओं के हाथों में ही थी। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीरनारायण सिंह को कौन नहीं जानता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जब गाँधीजी के नेतृत्व में सत्याग्रह की नींव पड़ी, तब भी जंगल सत्याग्रह के रूप में मध्यप्रांत के

छत्तीसगढ़ संभाग के असंख्य आदिवासियों ने कांग्रेस को आंदोलन का एक नया विकल्प दिया जो 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मध्यप्रांत का प्रमुख आंदोलन बना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के पन्नों में भले ही आदिवासियों के योगदान को नकार दिया गया हो परंतु मध्यप्रांत के आदिवासियों ने देश की आजादी में अपना संपूर्ण योगदान दिया था।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. शुक्ला सुरेश चंद्र व शुक्ला अर्चना, छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास, मातुश्री प्रकाशन, रायपुर, 2018 पृष्ठ 48
2. मिश्र रामेंद्रनाथ व मिश्र सुनीत, वीरनारायण सिंह, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1998, पृष्ठ 32-33
3. मिश्र सुरेश, उन्नीसवीं सदी में भारत में आदिवासी विद्रोह, स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन 2008 पृष्ठ 68
4. सक्सेना धनश्याम, जंगल सत्य और जंगल सत्याग्रह, स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन 2008 पृष्ठ 94-96
5. शुक्ला सुरेश चंद्र पूर्वोक्त पृष्ठ 48
6. सक्सेना धनश्याम पूर्वोक्त पृष्ठ 105-108
7. शर्मा अरविंद, छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास, अरपा पॉकेट बुक्स 2005-2006 पृष्ठ 147

